भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3310

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में डायलिसिस सुविधाएँ

3310. श्री नवसकनी के.:

श्री जी. सेल्वमः

श्री सी. एन. अन् नादुरईः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मधुमेह रोगियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और उनमें से कई को अंततः गुर्दे से संबंधित जटिलताओं के कारण डायलिसिस की आवश्यकता होती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने तमिलनाडु सहित देश भर के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस केंद्रों और नेफ्रोलॉजी सेवाओं की वर्तमान उपलब्धता का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में संचालित डायलिसिस केंद्रों की संख्या कितनी है और उक्त सेवाओं का लाभ उठाने वाले रोगियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का तमिलनाडु के ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में डायलिसिस सुविधाओं का विस्तार या उन्नयन करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) विगत पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम किसी अन्य योजना के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी निधि आवंटित/जारी और उपयोग की गई है, और

(च) क्या सरकार का शीघ्र निदान और समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए मधुमेह और नेफ्रोलॉजी देखभाल को एक सामान्य एनसीडी कार्य ढांचे के तहत एकीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद - भारत मधुमेह (आईसीएमआर – इंडियाबी) द्वारा 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, मधुमेह की प्रबलता 10.1 करोड़ है। विस्तृत रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है-

https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(23)00119-5/fulltext.

समय के साथ, मधुमेह हृदय, रक्त वाहिकाओं, आँखों, गुर्दों और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुँचा सकता है और इनमें से कई को गुर्दे संबंधी जटिलताओं के कारण अंततः डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है, विशेष रूप से उन रोगियों में जिनमें 'अंतिम चरण के गुर्दे की बीमारी' (एंड स्टेज रेनल डिसिस) है।

(ख) और (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय समय-समय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा समीक्षा मिशन, क्षेत्रीय दौरों और टेली-परामर्श के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम का नियमित मूल्यांकन करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी डायलिसिस केंद्रों को एकीकृत करके (पीएमएनडीपी) पोर्टल विकसित किया गया है। पीएमएनडीपी पोर्टल में डायलिसिस रोगियों को विशिष्ट आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (आभा) आईडी के साथ पंजीकृत करने और सभी डायलिसिस सत्रों को रिकॉर्ड करने की सुविधा है। इस पोर्टल के परिणामस्वरूप डायलिसिस रोगियों को कहीं भी आने-जाने की सहजता प्रदान की गई है और उसके बाद किए जाने वाली देखभाल व निगरानी में सुधार हुआ है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन-हाउस मॉडल के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के तहत राज्य भर में 142 हीमोडायलिसिस केंद्र कार्य कर रहें हैं। इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और उनके संबद्ध संस्थानों में 41 इकाइयाँ, जिला अस्पतालों में 33 इकाइयाँ और उप-जिला अस्पतालों में 59 इकाइयाँ शामिल हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में 9 हीमोडायलिसिस इकाइयां काम कर रही हैं।

(घ): पीएमएनडीपी कार्यक्रम का उद्देश्य डायलिसिस सेवाओं (हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों) तक पहुंच में सुधार करना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी जिला अस्पतालों में शुरुआत में हीमोडायलिसिस केंद्र स्थापित करने और संतृप्ति पैमाने पर तालुका स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर स्थापित करने की सिफारिश की है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। हालांकि, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को डायलिसिस सेवाओं (हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए डायलिसिस बोझ और जहां सुविधा नहीं है उस मूल्यांकन के आधार पर उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के अनुसार डायलिसिस सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया जा सके।

(ङ): तमिलनाडु सरकार के अनुसार, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का वर्षवार विवरण इस प्रकार हैः

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत (लाख रुपए में)	जारी (लाख रुपए में)	उपयोग की गई निधियों का प्रतिशत
2020-21	876.28	876.28	100%
2021-22	3644.85	3644.85	100%
2022-23	865.60	865.60	100%
2023-24	530.68	530.68	100%
2024-25	1670.99	1670.99	100%

(च): देश में एनएचएम और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की एक सुविधा के रूप में, सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसर की रोकथाम, नियंत्रण और जाँच के लिए एक जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सामान्य गैर-संचारी रोगों की जाँच के लिए लक्षित किया जाता है। इन सामान्य गैर-संचारी रोगों की जाँच आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सेवा प्रदान करने का एक अभिन्न अंग है, जो गैर-संचारी रोगों के जोखिम कारकों के बारे में जागरूकता पैदा करता है।

यह मानते हुए कि अनियंत्रित उच्च रक्तचाप और मधुमेह क्रोनिक किडनी रोग (सीकेडी) और गुर्दे की विफलता के प्रमुख कारण हैं, तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत गैर संचारी रोगों (एनसीडी) की जटिलताओं की लक्षित जांच शुरू की है, जिसमें मधुमेह संबंधी नेत्र जटिलताओं का शीघ्र पता लगाने के लिए रेटिनोपैथी जांच, डायबिटिक फुट के जोखिम की पहचान के लिए न्यूरोपैथी जांच और नेफ्रोपैथी जांच पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

विशेष रूप से नेफ्रोपैथी के समाधान हेतु, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर बनाई गई प्रक्रिया में सीकेडी जाँच लागू की गई है। इस पहल में, सामुदायिक स्तर पर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक (डब्ल्यूएचवी) अनुवर्ती दौरों के दौरान उच्च रक्तचाप और मधुमेह के पुष्ट रोगियों की पहचान करती हैं और उन्हें आगे की जाँच के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य उप-केंद्रों (एचएससी) या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में भेजती हैं। सुविधा केंद्रों पर, नेफ्रोपैथी के लक्षणों के लिए उच्च जोखिम वाले रोगियों की जाँच हेतु एचएससी और पीएचसी में मूत्र डिपस्टिक परीक्षण किए जाते हैं।

*****